

INDUSTRIAL TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT

The 18th April, 1994

No. 28/4/83-2IT.—The Governor of Haryana is pleased to extend the tenure of the State Council for Vocational Education in the State Constitute,—*vide* Government Notification No. 28/4/83-2IT, dated 11th October, 1991 published in *Haryana Government Gazette* of 22nd October, 1991 on existing terms and conditions for a period of two years.

TARSEM LAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Industrial Training and Vocational Education Department.

HEALTH DEPARTMENT

The 9th May, 1994

No. 36/31/2HBII/92.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Central Act 37 of 1954) the Governor of Haryana hereby authorises the Food Inspectors appointed as such,—*vide* Haryana Government Health Department Notification No. 36/31/2HBII/92, dated April 1, 1994 published in *Haryana Government Gazette*, dated April 12, 1994 in the Local Areas of their respective Jurisdiction excepting Railway Stations and Railway Premises.

RAGHBIR SINGH,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 9 मई, 1994

संख्या 36/31/2एच०बी-II-94.—बांद्रा प्रपत्रियन अधिनियम, 1954(1954 केन्द्रीय अधिनियम, 37) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा बांद्रा निरीक्षकों जिनकी ऐसी नियुक्ति हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 36/31/2एच०बी-II-92, दिनांक 1 अप्रैल, 1994 जो हरियाणा सरकार के गजट में दिनांक 12, अप्रैल 1994 में प्रकाशित हुई, द्वारा की गई, को रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों को छोड़कर उनके क्षेत्राधिकार के स्थानीय क्षेत्रों के लिये प्राधिकार करते हैं।

रघबीर सिंह,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

REVENUE DEPARTMENT

The 6th May, 1994

No. 2177-R-III-94/9783.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land in the locality specified below is needed by the Government, at public expence, for a public purpose, namely, for the construction of Government quarters for the Government Officials at Naraingarh, Tehsil Naraingarh, District Ambala, for which Haryana Government, Revenue Department Notification No. 7330-R-III-93/17780, dated the 26th/27th August, 1993 under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, has been published, it is hereby declared that the land described in the specifications below is needed for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Ambala.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village and Hadbast No.	Rectangle No./ Khasra No.	Area
				K.—M.
Ambala	Naraingarh	Naraingarh, H. B. No. 88	18//21/1 19//25/2/2 25//5/2/1 6/1/1 26//1	1—8 GM 0—19 4—10 1—05 1—19
				Total .. 10—1

A. BANERJEE,
Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

राजस्व विभाग

दिनांक 6 मई, 1994

संख्या 2177-RIII/94/9783.—चूंकि हरियाणा सरकार के राजस्वाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् नरायणगढ़, तहसील नरायणगढ़, जिला अम्बाला, में सरकारी कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण के लिये अपेक्षित है जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 7330-र-3-93/17780, दिनांक 26 अगस्त 1993, प्रकाशित की गई है उसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 6 के उपवन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

भूमि के नवशों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलमटर, अम्बाला, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव तथा हृदबस्त सं०	आयत/खसरा सं०	क्षेत्रफल
				क० म०
अम्बाला	नरायणगढ़	नरायणगढ़, ह० सं० 88	18//21/1 19//25/2/2 25//5/2/1 6/1/1 26//1	1 8 ग० म० आबादी 0 19 ,,, 4 10 ,,, 1 05 ,,, 1 19 ,,,
				Total .. 10—1

ए. बैनरजी,
सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।